RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 06 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 13 | अंक-69 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

लोन सस्ते होंगे: RBI ने रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% किया, 20 लाख लोन पर 74 हजार तक का फायदा

MPC की सर्वसम्मति से फैसला, FY26 GDP अनुमान 7.3% और महंगाई 2.0% पर; 1 लाख करोड़ OMO और $5 बिलियन स्वैप से लिक्विडिटी बढ़ी

नई दिल्ली: मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है, जिससे यह 5.25 प्रतिशत पर आ गया। यह 2025 में चौथा रेट कट है, जो लोन की EMI को कम करेगा और अर्थव्यवस्था को गति देगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को घोषणा की कि FY26 में GDP वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहेगी, जो पहले के अनुमान से 0.5 प्रतिशत अधिक है। मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी।

आर बी आई गवर्नर ने कहा, अक्टूबर में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची। घरेलू मांग मजबूत है, लेकिन वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच सतर्क रहना होगा।MPC ने न्यूट्रल स्टांस बनाए रखा है। कटौती से बैंक लोन दरें घटेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपये के 20 साल के होम लोन पर सालाना ब्याज 74,000 रुपये कम हो सकता है। कार, पर्सनल और बिजनेस लोन पर भी असर पड़ेगा।Q2 में GDP 8.2 प्रतिशत बढ़ी, जो छह तिमाहियों का उच्चतम है। करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3 प्रतिशत रहा। विनिमय भंडार 686 अरब डॉलर है। हालांकि, रुपये की गिरावट (90 के पार) और US टैरिफ चिंता का विषय हैं। आर बी आई गवर्नर ने कहा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस से 1 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे।विशेषज्ञों का कहना है कि यह कटौती मध्यम वर्ग के लिए सकारात्मक है। FY26 में 7.3 प्रतिशत विकास से निवेश बढ़ेगा। लेकिन मुद्रास्फीति पर नजर रखनी होगी। शेयर बाजार में सेंसेक्स 313 अंक चढ़ा। यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।

स्टार्टअप इंडिया ने रचा इतिहास: DPIIT ने 1,97,692 स्टार्टअप्स को मान्यता दी

31 अक्टूबर 2025 तक का आंकड़ा, 49% टियर-2/3 शहरों से; FFS, SISFS और CGSS स्कीमों से फंडिंग और रोजगार सृजन को गति

नई दिल्ली: स्टार्टअप इंडिया पहल ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने 31 अक्टूबर 2025 तक 1,97,692 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है, जो भारत के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की तेजी से वृद्धि को दर्शाता है।

यह मान्यता G.S.R. 501(E) के अनुसार पात्रता शर्तों पर आधारित है, जिसमें 10 वर्ष से कम पुरानी कंपनियां, 100 करोड़ तक टर्नओवर वाली और नवीन उत्पाद/सेवा वाली संस्थाएं शामिल हैं। इनमें से 49% टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं, जो ग्रामीण और छोटे शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा दर्शाता है। स्टार्टअप इंडिया, जो 2016 में लॉन्च हुई, ने 763 जिलों में 1.7 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं, जिनमें 40% प्रौद्योगिकी से जुड़ी हैं।

सरकार तीन प्रमुख योजनाओं: फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) के माध्यम से फंडिंग और सहायता प्रदान कर रही है। FFS के तहत 10,000 करोड़ का कोरपस जुटाया गया, जो स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल उपलब्ध कराता है। SISFS और CGSS कॉलेटरल-फ्री लोन सुनिश्चित करती हैं।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि स्टार्टअप्स को तीन वर्षों के लिए आयकर छूट, कैपिटल गेन टैक्स राहत और IPR फास्ट-ट्रैकिंग जैसे लाभ मिल रहे हैं। 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप नीतियां लागू हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप अवॉर्ड्स ने 68 केंद्रों में इनोवेशन को मान्यता दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि भारत को 2030 तक 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाने में मदद करेगी। स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमिता को लोकतांत्रिक बनाया है।

LIC ने रामकृष्णन चंदर को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया

1 दिसंबर से प्रभावी, 2027 तक कार्यकाल; 35 वर्षों का अनुभव, निवेश और अंतरराष्ट्रीय संचालन में विशेषज्ञता

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने रामकृष्णन चंदर को मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के अधिसूचना के अनुसार, चंदर का यह कार्यभार 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी है। उनका कार्यकाल सुपरएनुएशन (30 सितंबर 2027) तक या आगे के आदेश तक रहेगा। नियुक्ति से पहले चंदर LIC के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इन्वेस्टमेंट-फ्रंट ऑफिस) और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) थे।

LIC ने मंगलवार को बीएसई फाइलिंग में कहा कि चंदर 1990 में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। उनके पास मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और अंतरराष्ट्रीय संचालन में 35 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने सीनियर डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर (मार्केटिंग और पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स) तथा एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इंटरनेशनल ऑपरेशंस) जैसे पद संभाले। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो चंदर LIC के स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का नेतृत्व कर चुके हैं।

LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा, चंदर का अनुभव कंपनी के निवेश रणनीति और वैश्विक विस्तार को मजबूत करेगा। LIC के पास वर्तमान में चार MD हैं: सतपाल भनू, रत्नाकर पटनायक, दिनेश पंत और आर. डोरैस्वामी (CEO और MD)। भनू का कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त होगा।

FY26 की पहली छमाही में LIC का लाभ 16% बढ़कर 21,040 करोड़ रुपये रहा। Q2 में फर्स्ट ईयर प्रीमियम 10,884 करोड़ और रिन्यूअल प्रीमियम 65,320 करोड़ हो गया। चंदर का नेतृत्व कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राहक केंद्रित पहल को गति देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियुक्ति LIC को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। शेयर बाजार में LIC के शेयर 1.2% चढ़े। यह कदम बीमा क्षेत्र में स्थिरता का संकेत है।

आरबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के सीईओ के रूप में विक्रम साहू की नियुक्ति को मंजूरी दी

आंतरिक मेमो से खुलासा, 25 वर्षों का अनुभव; कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को मजबूती, भारत में 100 अरब डॉलर का व्यवसाय

मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक ऑफ अमेरिका (BoA) के भारत संचालन के लिए विक्रम साहू को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। यह खुलासा बैंक के आंतरिक मेमो से हुआ, जो कर्मचारियों को सर्कुलेट किया गया। साहू की नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जो कंपनी के कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट को नई दिशा देगी।

साहू, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है, वर्तमान में बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के इंडिया कॉन्ट्री हेड हैं। उन्होंने HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे वैश्विक बैंकों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आंतरिक मेमो में कहा गया कि साहू का नेतृत्व भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के 100 अरब डॉलर के व्यवसाय को मजबूत करेगा, खासकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पर फोकस के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया, जो 2006 से सक्रिय है, कॉर्पोरेट लोनिंग, ट्रेजरी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मजबूत है। FY25 में इसका राजस्व 15% बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो गया। साहू की नियुक्ति RBI के सख्त नियमों के अनुरूप है, जो विदेशी बैंकों के भारत संचालन को नियंत्रित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत को वैश्विक फाइनेंशियल हब बनाने में मदद करेगा।

Sun Pharma Arm Pours Rs 3,000 Cr into Madhya Pradesh Mega Plant

New API & Formulation Facility at Pithampur by 2028; 1,500 Jobs, Export-Focused Production to Strengthen Global Supply Chain

Indore: Sun Pharmaceutical Industries Ltd announced that its wholly-owned subsidiary will invest Rs 3,000 crore to establish a greenfield active pharmaceutical ingredient (API) and formulation manufacturing plant in Pithampur, Madhya Pradesh. The project, approved by the board on Tuesday, is expected to be commissioned in phases by 2028, creating approximately 1,500 direct and indirect jobs. Spread over 100 acres in the SEZ at Pithampur Industrial Area, the facility will focus on high-value oncology, cardiology, and specialty generics, with a significant portion earmarked for exports to regulated markets including the US and Europe. This strategic investment will enhance our backward integration, reduce dependency on imported APIs, and reinforce India's position as the pharmacy of the world, said Dilip Shanghvi, Managing Director, Sun Pharma.

The plant will incorporate cutting-edge automation, zero-liquid discharge systems, and renewable energy usage, aligning with Sun Pharma's net-zero goals by 2040. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav welcomed the move, stating it would position the state as a pharma hub alongside Gujarat and Telangana.

Sun Pharma, India's largest drug maker by market cap, currently operates 44 global manufacturing sites. The new unit will boost its domestic capacity by 15-20% and support the PLI scheme for critical APIs. Shares of Sun Pharma rose 2.4% to Rs 1,875 on BSE following the announcement. Analysts see the investment as a long-term margin booster amid rising global demand for complex generics.

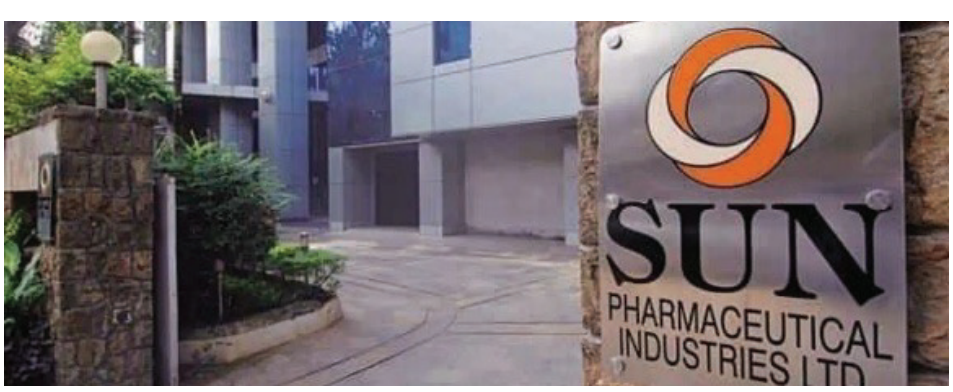

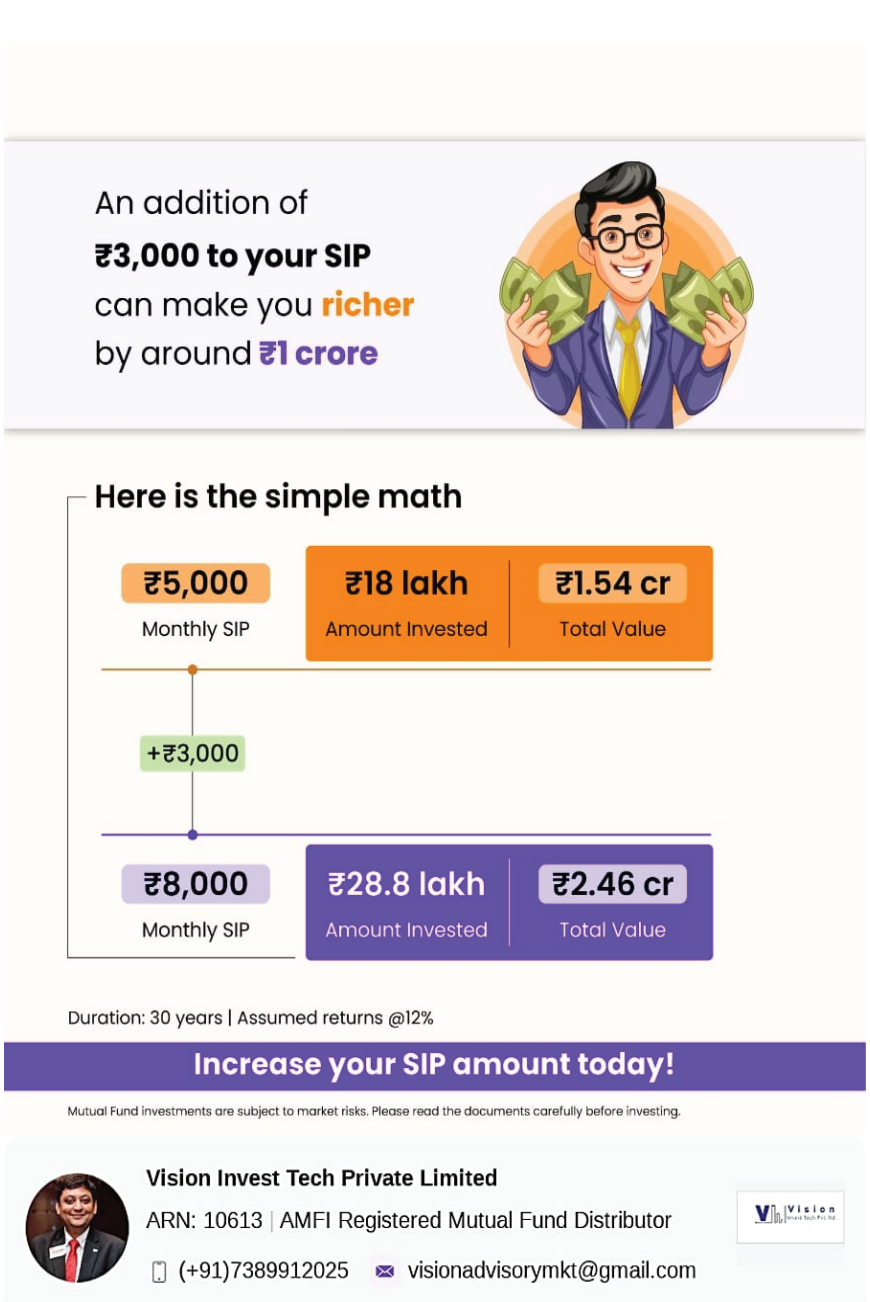

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

The Big AI Revolution: Which Indian Stocks & ETFs Will Benefit?

Artificial Intelligence (AI) is becoming the most powerful force shaping the global economy. From smartphones and healthcare to banking, transport, and retail, AI is changing how companies operate and how people live. India, with its large digital population and strong IT talent, is well placed to become a major player in this global shift. As AI adoption grows, several Indian stocks and ETFs are expected to benefit, offering opportunities for long-term investors.

AI is already visible in everyday life. Banks use it to detect fraud and approve loans faster. Retail companies use it to manage inventory. Hospitals use AI tools to analyse scans and support diagnosis. Even government services are adopting AI for digital governance. This creates demand for technology providers, data centers, electronics, and automation tools. As spending on AI increases, certain sectors of the Indian stock market are positioned to gain the most.

The first and most direct beneficiaries are India's IT giants. Companies like TCS, Infosys, HCL Tech, and Wipro are building AI platforms, automation tools, and consulting services for global clients. With businesses worldwide increasing investment in generative AI and digital transformation, these Indian IT players are expected to see stronger revenue growth. Their long record of working with Fortune 500 clients makes them natural winners of the AI boom.

The second major beneficiary will be data center and cloud infrastructure companies. AI requires large computing power, high-speed servers, and secure data storage. India is currently building multiple data center parks, supported by government incentives. Companies like Adani Enterprises, Reliance Industries (Jio Platforms), L&T Technology Services, and Sify Technologies are expanding in this space. As more companies use AI-based tools, the demand for data centers will multiply, turning this into a high-growth segment.

A third promising area is semiconductors and electronics manufacturing. AI tools depend on powerful chips, and India is taking steps to build its own semiconductor ecosystem. Companies such as Tata Elxsi, Tata Electronics, Dixon Technologies, and SPEL Semiconductor are expected to benefit as India increases chip design, assembly, and testing capacity. Though the sector is still in an early stage, the long-term potential is significant.

Another set of beneficiaries are businesses that use AI to improve efficiency. Banks like HDFC Bank and ICICI Bank use AI for risk assessment and customer service. E-commerce and retail companies such as Zomato, DMart, and Nykaa rely on data analytics for faster delivery and inventory planning. These companies may grow faster as AI reduces cost and improves productivity.

For investors who prefer diversification, AI-linked ETFs offer a simple way to participate in the trend. Popular options include Nippon India Nifty IT ETF, ICICI Prudential Nifty IT ETF, Kotak NV20 ETF, and Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF, which provides exposure to global AI leaders such as Microsoft, Nvidia, and Amazon. These ETFs allow investors to benefit from the broader AI theme without selecting individual stocks.

As India moves deeper into the digital age, AI is set to become a key driver of corporate earnings and stock market growth. The companies building AI technology and the companies adopting it will form the new leaders of India's next economic phase. For investors, the message is clear: the AI revolution is here, and those who understand it early may benefit the most.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

एशियाई विकास बैंक ने भारत के रूफटॉप सोलर को गति देने के लिए 650 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया

2027 तक 10 मिलियन घरों को सस्ती साफ ऊर्जा, PM सूर्य घर योजना को बल; 30 GW लक्ष्य, 28.8 मिलियन टन CO2 कटौती का अनुमान

नई दिल्ली: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत सरकार को रूफटॉप सोलर अपनाने को तेज करने के लिए 650 मिलियन डॉलर (लगभग 5,780 करोड़ रुपये) का नीति-आधारित ऋण मंजूर किया है। यह ऋण प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को समर्थन देगा, जिसका लक्ष्य 2027 तक 10 मिलियन घरों को साफ, सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। ADB के देश निदेशक मियो ओका ने कहा, "यह कार्यक्रम वित्तीय बाधाओं और नियामक कमियों को दूर कर रूफटॉप सोलर को लाखों घरों के लिए सुलभ बनाएगा, हरित रोजगार सृजित करेगा और महिलाओं को सशक्त बनाएगा।"

ऋण में 3 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता भी शामिल है, जो सुधारों के कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता निर्माण और लिंग-समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देगी। कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्रों में आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए एकसमान संचालन दिशानिर्देश और गुणवत्ता मानक विकसित करना, निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों के लिए गारंटी-रहित, कम ब्याज वाले ऋण सुविधा प्रदान करना शामिल है। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों के अनुरूप, यह कार्यक्रम 5,000 कर्मियों (जिनमें 1,500 महिलाएं) की क्षमता बढ़ाएगा, उपयोगिता-आधारित एग्रीगेशन मॉडल, मॉडल सोलर गांवों का विकास और मजबूत विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा।

ADB का हस्तक्षेप देशव्यापी 30 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे प्रतिवर्ष 28.8 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे लाखों घरों को सस्ती सौर ऊर्जा मिलेगी। ओका ने कहा, "यह कार्यक्रम भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को तेज कर रहा है, बाधाओं को दूर कर रहा है।"

यह ऋण महाराष्ट्र के किसानों को दिन के समय सौर बिजली प्रदान करने के लिए ADB के पिछले 460 मिलियन डॉलर के ऋण का विस्तार है। ADB का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम हरित ऊर्जा को लोकतांत्रिक बनाएगा।

Adani Group Seals Rs 231 Cr Acquisition of Trade Castle Tech Park to Fuel Data Centre Boom

AdaniConneX Gains Full Control of Infrastructure Developer; Strategic Land and Licenses to Accelerate 1 GW National Platform

Mumbai: Adani Enterprises Ltd (AEL), the flagship of Gautam Adani's conglomerate, has completed the acquisition of Trade Castle Tech Park Pvt Ltd (TCTPPL) for Rs 231.34 crore, bolstering its data centre ambitions through the joint venture AdaniConneX. The deal, announced in a stock exchange filing, marks a key step in expanding infrastructure capabilities amid surging demand for digital assets.

AdaniConneX Pvt Ltd, a 50:50 partnership between Adani Group and US-based EdgeConneX, acquired 100% stake in TCTPPL, making it a step-down joint venture. The share purchase agreement, signed on November 21 with TCTPPL's existing shareholders Shree Naman Developers and Jayesh Shah has now been finalized. Incorporated in Mumbai on October 16, 2023, TCTPPL focuses on infrastructure development and holds substantial land parcels along with essential licenses, providing AdaniConneX a ready platform for rapid scaling.

While TCTPPL has yet to commence commercial activities, its land holdings and secured licenses give a head start to ACX, AEL stated. AdaniConneX aims to build a 1 GW national data centre platform over the next decade, tapping into India's booming digital economy projected to reach $1 trillion by 2030. This acquisition aligns with the group's aggressive push into hyperscale facilities, supported by partnerships like Google and Microsoft.

The move comes amid Adani's broader diversification from ports and power into tech infrastructure. Analysts estimate the deal could unlock Rs 5,000-7,000 crore in future value through data centre developments. Shares of Adani Enterprises rose 1.2% to Rs 2,950 on BSE, reflecting investor confidence in the group's strategic expansions.

As global data consumption surges, this acquisition positions AdaniConneX to capture a significant slice of India's Rs 10 lakh crore data centre market by FY30, fostering job creation and technological self-reliance.

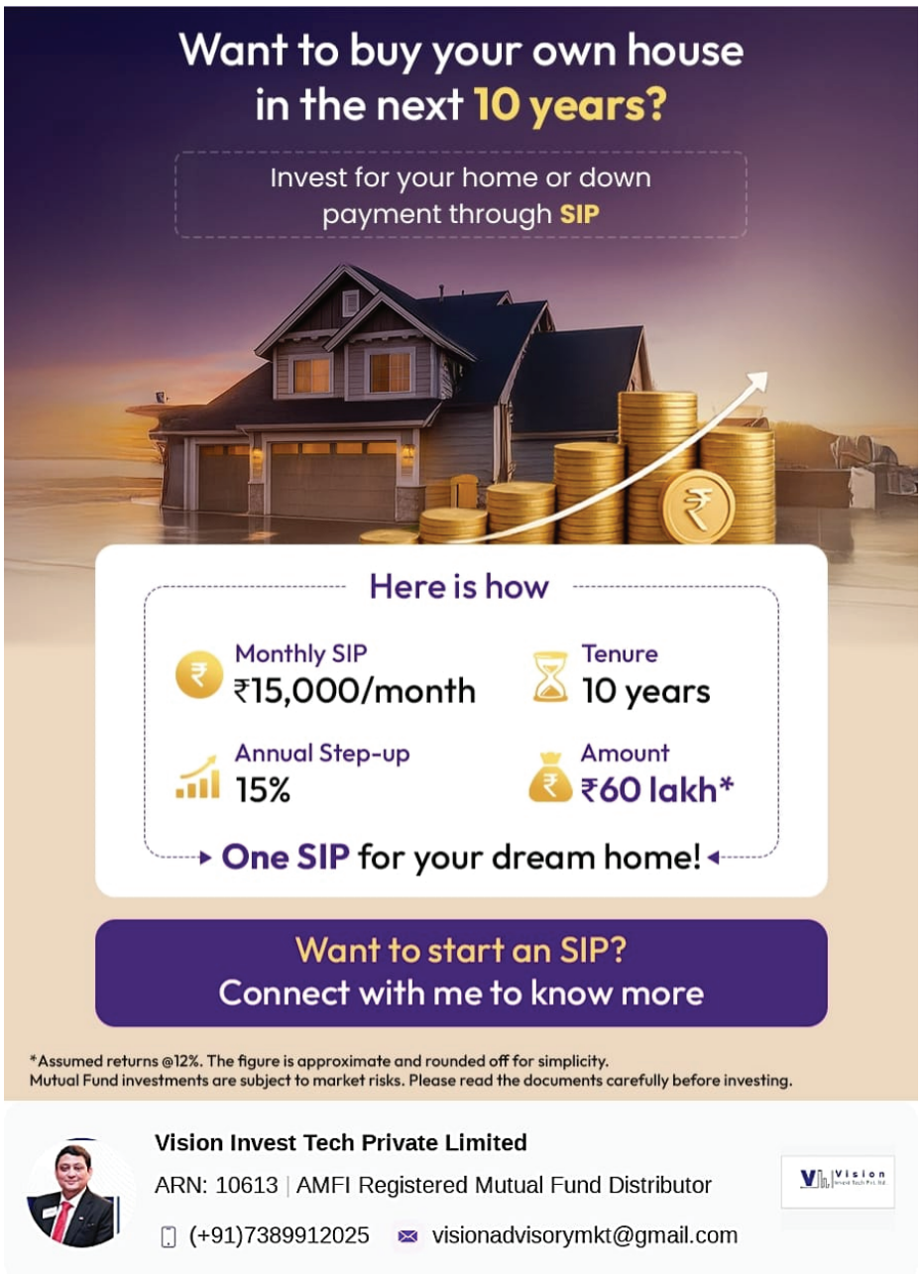

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट ऐवेन्युस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES

Share Your Knowledge with INVESTMENT AVENUES

We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in

write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

Moonrider's $6M Series A Boost: EV Tractor Startup Accelerates Farm Revolution

Pi Ventures-Led Round Fuels Battery and Powertrain Refinements; Targets Commercial Launch of 27HP-75HP Models by February 2026

Bengaluru: Electric tractor startup Moonrider has raised $6 million (about Rs 50 crore) in a Series A funding round led by deep-tech investor Pi Ventures, with participation from Singularity AMC and existing backers AdvantEdge Founders and Micelio Fund. The Bengaluru-based company, founded in 2023 by former Volvo executives Anoop Srikantaswamy and Ravi Kulkarni, aims to deploy the capital to refine its proprietary battery and powertrain technologies tailored for Indian farming conditions.

Moonrider's platform is designed to slash land preparation and farming costs by up to 80% compared to diesel tractors, while maintaining price parity. Unlike conventional EVs that cost 1.5-2x more, Moonrider's heavy-duty models ranging from 27HP to 75HP offer endurance on a single charge, addressing key pain points like high upfront costs and limited infrastructure in rural areas. "Every decision at Moonrider revolves around one question: does this save farmers' money? Electric tractors do," said Anoop Srikantaswamy, Founder and CEO. The funds will accelerate durability testing across diverse soils and climates, paving the way for a February 2026 commercial launch.

India's tractor market sells about one million diesel units annually, but EV adoption is nascent despite government initiatives like PM E-DRIVE. Moonrider's vertical integration in drivetrain, batteries, and software positions it to capture this shift, especially as fuel costs erode farm profitability. The startup, which raised $2.2 million in seed funding in January 2025, claims its tractors deliver more power for tasks like deep plowing and harvesting.

Sohil Bhagat, MD at Pi Ventures, highlighted the potential: Cost-effective electric tractors can reshape farm economics in India and developing markets." Suyash Kela of Singularity AMC echoed, "Electrification in commercial vehicles is a core theme, and tractors are a compelling opportunity."

With India's EV market eyeing $132 billion by 2030, Moonrider's focus on the underserved tractor segment could drive sustainable agriculture. The company plans to partner with fleet owners for rentals, making EVs accessible to small farmers. Shares of related EV firms rose 2-3% on the news, signaling investor optimism in agritech innovation.

Two-Wheeler Giants Accelerate: Hero MotoCorp Zooms 31%, Royal Enfield Revs 22% in November 2025

Festive Afterglow, Rural Recovery and GST Cuts Drive Record Volumes; Combined Sales Cross 10 Lakh Units

New Delhi: India's two-wheeler market continued its festive-season momentum into November, with Hero MotoCorp and Royal Enfield posting blockbuster numbers, signalling a strong rural and semi-urban revival.

Hero MotoCorp, the world's largest two-wheeler manufacturer, dispatched 6,05,570 units in November 2025, registering a robust 31% year-on-year growth (November 2024: 4,62,608 units). Domestic sales surged 32% to 5,92,000 units, while exports grew 12%. The Splendor, HF Deluxe and Passion portfolio, bolstered by higher MSP and record kharif output, led the charge in rural pockets.

Royal Enfield, the premium motorcycle arm of Eicher Motors, clocked 1,01,222 units, up 22% from 82,909 units last year. The 350-cc segment (Classic, Bullet, Hunter, Meteor) remained the growth engine, contributing over 88% of volumes. Domestic sales rose 21% to 91,213 units and exports jumped 32% to 10,009 units, driven by strong demand for the new Classic 350 and Himalayan 450.

Both companies credited the recent GST rationalization (28% to 18% on entry-level bikes), improved financing availability and wedding-season purchases for the upswing. Industry analysts estimate the two-wheeler segment grew 25-27% YoY in November, crossing 20 lakh units overall.

With inventories normalised at 30-35 days and new launches lined up for Q4, Hero and Royal Enfield are confident of sustaining double-digit growth into FY26.

Rupee's Relentless Slide: Why the INR is Plunging and Its Ripple Effects on India's Economy

FII Outflows, Surging Imports, and US Trade Tensions Fuel Depreciation; Boost to Exports Offset by Inflation and Debt Woes

New Delhi: The Indian rupee has hit a fresh low of ₹90.21 against the US dollar, marking a 3.5% depreciation in 2025 so far and breaching a critical psychological barrier. This slide, despite robust 7.8% GDP growth in Q2, underscores vulnerabilities in India's external balances, raising alarms for policymakers and households alike.

Multiple factors are driving this downturn. Foreign institutional investors (FIIs) have withdrawn a staggering $1.8 billion from equities, fueled by global uncertainties and high valuations, increasing dollar demand. Imports ballooned to $76.1 billion in October a 16.6% surge led by festive gold buying and record oil prices, widening the trade deficit to $41.7 billion. Delays in the India-US trade deal, coupled with impending 50% US tariffs, have eroded investor confidence, while a stronger dollar (despite its recent dip below 100) adds pressure. RBI's restrained interventions, prioritizing reserves at $698 billion, have allowed a gradual fall to support exports.

The economic fallout is multifaceted. A weaker rupee inflates import costs, pushing crude oil and electronics prices up by 5-7%, fueling inflation to 5.5% and eroding purchasing power. Servicing $620 billion external debt becomes costlier, adding Rs 10,000 crore annually in interest burdens. For consumers, outbound education and travel expenses rise 3-5%, hitting middle-class wallets hard. Remittances from $100 billion overseas inflows, however, gain 3.5% value in rupees.

On the flip side, depreciation enhances export competitiveness, potentially lifting IT, textiles, and pharma sectors by 2-3% in earnings. Yet, experts warn of risks: prolonged weakness could deter FDI, currently at $18.6 billion in H1, and amplify inflation if oil hits $80/barrel.

RBI Governor has signaled vigilance, with reserves ample for stability. Fiscal measures like import curbs on gold and duty tweaks on electronics aim to ease pressure. As India eyes 7% FY26 growth, a balanced rupee trajectory via export boosts and FII inflows remains key to sustaining momentum without sparking imported inflation.

Asian Paints Bets Big on Cricket: BCCI Sponsorship is Our Game-Changing Hook

₹1,200-cr deal for India home matches till 2028; Exec says cricket will drive brand salience and category creation

Bengaluru: Asian Paints has emerged as the official sponsor of the Board of Control for Cricket in India (BCCI) in a blockbuster ₹1,200-crore deal covering all India home internationals until 2028. The three-year agreement, confirmed on Monday, marks one of the richest non-beverage sponsorships in Indian cricket history.

Speaking to reporters, Asian Paints Chief Marketing Officer Amit Syngle called the partnership a once-in-a-generation opportunity. Cricket is not just a sport in India; it is the ultimate cultural connector. This sponsorship gives us a strong hook to seed our category in this space in a big way, he said. The brand plans to leverage stadium branding, LED perimeter boards, and digital activations to reinforce its positioning as the nation's leading home beautification partner.

The deal comes at a time when Asian Paints is pushing premium offerings like waterproofing solutions and luxury emulsions. Every time India plays at home, millions see their walls before they see the stadium walls. We want to own that emotional moment, Syngle added.

The pact also includes associate sponsorship rights for IPL and domestic tournaments. Industry experts estimate the association will deliver over 6,000 hours of annual visibility. Shares of Asian Paints rose 2.8% to ₹3,185 on BSE, reflecting investor optimism. With rival Berger Paints also active in sports, the BCCI deal intensifies the battle for mindshare in India's ₹70,000-crore paints market.

रुपये की गिरावट पर उदय कोटक का आह्वान: भारतीय कंपनियां आगे बढ़ें, विदेशी निवेशक बाजार पर हावी

90 के पार पहुंची मुद्रा, FII बिकवाली और PE फंड्स का दबाव; घरेलू निवेशक खरीद रहे, लेकिन लंबी दौड़ में भारतीय व्यवसायों को सतर्क रहना होगा

मुंबई : रुपये की लगातार गिरावट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौती दी है। मंगलवार को यह 90 के पार पहुंच गई, जो 2025 में 3.5% की कमजोरी दर्शाती है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने भारतीय कंपनियों से अपील की है कि वे अपनी आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, क्योंकि विदेशी निवेशक बाजार पर हावी हो रहे हैं। कोटक ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, रुपए के 90 पार पहुंचने का तत्काल कारण FPI और FDI रूट से PE फंड्स की बिकवाली है। घरेलू निवेशक खरीद रहे हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी 'स्मार्ट' लग रहे हैं। निफ्टी का एक साल का डॉलर रिटर्न शून्य है। लेकिन यह लंबी दौड़ है। भारतीय व्यवसायों को अपनी आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा।

कोटक का बयान रुपये की गिरावट के बीच आया है, जो FII की $1.8 बिलियन की निकासी, बढ़ते आयात ($76.1 बिलियन अक्टूबर में) और US-भारत व्यापार सौदे में देरी से प्रेरित है। व्यापार घाटा $41.7 बिलियन तक पहुंच गया। RBI ने हस्तक्षेप सीमित रखा है, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले।

रुपए की कमजोरी के प्रभाव दोहरे हैं। निर्यातक कंपनियां लाभान्वित होंगी, क्योंकि IT, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर की कमाई 2-3% बढ़ सकती है। लेकिन आयातक क्षेत्रों—जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना—की लागत 5-7% उछलेगी, जो मुद्रास्फीति को 5.5% तक ले जाएगी। $620 बिलियन बाहरी कर्ज पर सालाना 10,000 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज बोझ पड़ेगा। उपभोक्ताओं के लिए विदेशी शिक्षा और यात्रा महंगी हो जाएगी।

कोटक ने चेतावनी दी कि FII और PE फंड्स की बिकवाली से बाजार अस्थिर है। Q2 में 7.8% GDP वृद्धि के बावजूद, रुपये की स्थिति चिंताजनक है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि $698 बिलियन के भंडार से स्थिरता सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात बढ़ावा और FII इनफ्लो से रुपये को संभाला जा सकता है। कोटक का आह्वान भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होने का संदेश है।

हिंदूजा ग्रुप का IndusInd Bank में रणनीतिक साझेदार तलाशने का प्लान: हिस्सेदारी पतली नहीं करेंगे

अल्पसंख्यक निवेशक के रूप में वैश्विक विशेषज्ञता वाली कंपनी, IIHL का स्टेक 16.5% पर स्थिर; रिलायंस कैपिटल अधिग्रहण के बाद विस्तार की रणनीति

मुंबई: हिंदूजा ग्रुप, जो IndusInd Bank का प्रमुख प्रमोटर है, बैंक में रणनीतिक साझेदार तलाश रहा है, लेकिन अपनी हिस्सेदारी को पतला नहीं करेगा। ग्रुप के चेयरमैन अशोक हिंदूजा ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, हम वैश्विक विशेषज्ञता वाली स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तलाश में हैं, जो अल्पसंख्यक निवेशक के रूप में आए। IIHL (IndusInd International Holdings) अपनी हिस्सेदारी पतला नहीं करेगी। वर्तमान में, हिंदूजा ग्रुप की इकाई IIHL और संबंधित कंपनियों के पास बैंक की 16.5% हिस्सेदारी है।

यह घोषणा बैंक के हालिया चुनौतियों जैसे डेरिवेटिव ट्रेड्स में अनियमितताओं से $230 मिलियन का लेखांकन घाटा के बीच आ रही है। ग्रुप का लक्ष्य बैंक को मजबूत करना है, जिसमें इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज बिजनेस को IndusInd ब्रांड के तहत एकीकृत करना शामिल है। हिंदूजा ने कहा, IIHL का विजन BFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस) के सभी पहलुओं को कवर (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस) के सभी पहलुओं को कवर करना है। रिलायंस कैपिटल अधिग्रहण और इनवेस्को के साथ साझेदारी के बाद, हम रीब्रांडिंग कर रहे हैं, ताकि सब कुछ IndusInd छतरी के नीचे आए।

हालांकि, RBI के दिशानिर्देशों के तहत प्रमोटर स्टेक 15% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन हिंदूजा ने 26% तक बढ़ाने की मांग की है। ग्रुप ने पहले RBI से अप्रूवल मांगा था, लेकिन कंडीशंस के कारण प्रक्रिया लंबी हो गई। अशोक हिंदूजा ने कहा, RBI ने अप्रूवल दिया था, लेकिन बोर्ड प्रक्रिया पूरी करनी है। हम पूंजी इन्फ्यूजन के लिए तैयार हैं।

IndusInd Bank का Q4 FY25 में 2,329 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अनियमितताओं से था। SEBI और RBI की जांच जारी है। ग्रुप ने बोर्ड और मैनेजमेंट पर भरोसा जताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर बैंक को स्थिरता देगा।

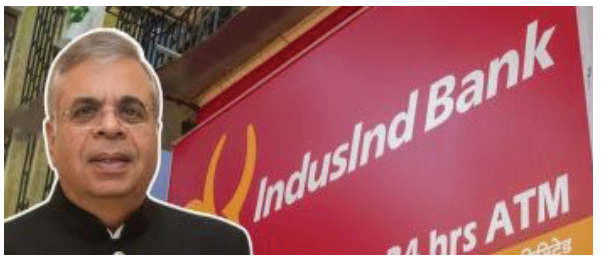

FDI नीति में निरंतर सुधार: भारत को निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाने पर जोर

वाणिज्य मंत्रालय की समीक्षा, प्रेस नोट 3 और PLI स्कीमों से सफलता; 2025 में 100 अरब डॉलर FDI का लक्ष्य

नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति को निरंतर समीक्षा के दायरे में रखा जा रहा है ताकि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बना रहे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई सेक्टर्स में FDI सीमा को उदार बनाया गया है, जिससे रक्षा, बीमा, पेंशन और स्पेस सेक्टर में 100% ऑटोमैटिक रूट की अनुमति मिली है।

अधिकारी ने कहा, हमारा उद्देश्य नीति को सरल, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाना है। PLI स्कीमों, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और GIFT सिटी जैसे कदमों से विदेशी कंपनियां भारत को प्राथमिकता दे रही हैं। अप्रैल-सितंबर 2025 में FDI इक्विटी इनफ्लो 35 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष से 18% अधिक है। सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका और नीदरलैंड्स शीर्ष स्रोत बने हुए हैं।

सरकार अब ई-कॉमर्स, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी में और छूट पर विचार कर रही है। हाल ही में डिफेंस प्रोडक्शन में 74% तक FDI की अनुमति और स्पेस सेक्टर में 100% FDI ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। मंत्रालय ने कहा कि 2025 में 100 अरब डॉलर FDI का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श जारी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिर नीति और 7%+ GDP वृद्धि वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रही है। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा।

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

AII level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	losing Rat	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	26186	26811	26569	26377	26135	25943	25701	25509
BANK NIFTY	59777	61468	60790	60284	59606	59100	58422	57916
SENSEX	85712	87628	86866	86289	85527	84950	84188	83611
FINNIFTY	27882	28785	28425	28154	27794	27523	27163	26892
MIDCAP	13999	14442	14280	14139	13977	13836	13674	13533
ACC	1800	1920	1894	1847	1821	1774	1748	1701
AXISBANK	1284	1331	1310	1297	1276	1263	1242	1229
ABCAPITAL	358	377	369	363	355	349	341	335
BHARTIARTL	2110	2173	2146	2128	2101	2083	2056	2038
BHEL	278	313	304	291	282	269	260	247
BIOCON	392	436	424	408	396	380	368	352
CDSL	1554	1729	1683	1619	1573	1509	1463	1399
DATAPATTERN	2760	3220	3122	2941	2843	2662	2564	2383
ESCORTS	3719	4060	3984	3851	3775	3642	3566	3433
EICHERMOTOR	7205	7520	7385	7295	7160	7070	6935	6845
FEDERAL BANK	259	268	265	262	259	256	253	250
GRINFRAPOJECT	1060	1130	1105	1083	1058	1036	1011	989
HDFCBANK	1001	1049	1034	1017	1002	985	970	953
HCLTECH	1681	1774	1732	1707	1665	1640	1598	1573
HINDUNILVR	2341	2650	2569	2455	2374	2260	2179	2065
HAL	4442	4702	4642	4542	4482	4382	4322	4222
HYUNDAI	2310	2501	2461	2385	2345	2269	2229	2153
IOC	163	169	167	165	163	161	159	157
ICICIBANK	1392	1439	1419	1406	1386	1373	1353	1340
INFY	1614	1721	1676	1645	1600	1569	1524	1493
ITC	405	416	411	408	403	400	395	392
KOTAKBNK	2156	2222	2194	2175	2147	2128	2100	2081
LICHOUSING	544	571	563	554	546	537	529	520
LT	4039	4247	4175	4107	4035	3967	3895	3827
LUPIN	2090	2165	2136	2113	2084	2061	2032	2009
MARUTI	16284	16946	16642	16463	16159	15980	15676	15497
M&M	3708	3963	3879	3793	3709	3623	3539	3453
MGL	1170	1237	1220	1195	1178	1153	1136	1111
MAZGAONDOC	2616	2804	2752	2684	2632	2564	2512	2444
PFC	353	380	373	363	356	346	339	329
RECLTD	354	377	370	362	355	347	340	332
RELIANCE	1545	1632	1604	1575	1547	1518	1490	1461
SBIN	972	1040	1015	994	969	948	923	902
SUNPHARMA	1803	1893	1867	1835	1809	1777	1751	1719
SHRIRAMFINANCE	853	918	892	872	846	826	800	780
TITAN	3813	4019	3964	3888	3833	3757	3702	3626
TCS	3241	3451	3361	3301	3211	3151	3061	3001
TATAMOTORS	354	374	369	362	357	350	345	338
UPL	759	795	779	769	753	743	727	717
VALIENT	268	311	297	282	268	253	239	224
WIPRO	260	276	269	264	257	252	245	240

गोल्ड ETF का AUM अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार, 27,500 करोड़ का रिकॉर्ड इनफ्लो

त्योहारों और वैश्विक अनिश्चितता से चमका सोना, 2025 में अब तक 42,300 करोड़ जुटे; निवेशकों ने इक्विटी MF से ज्यादा भरोसा गोल्ड पर दिखाया

मुंबई: भारत में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) अक्टूबर 2025 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में गोल्ड ETF में 27,500 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड नेट इनफ्लो दर्ज हुआ, जिससे कुल AUM 1,03,780 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह पिछले महीने के 76,280 करोड़ से 36% अधिक है।

त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी, अमेरिकी फेड रेट कट की उम्मीदें, डॉलर की कमजोरी और मध्य-पूर्व तनाव ने सोने को सुरक्षित निवेश का सबसे मजबूत विकल्प बना दिया। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक गोल्ड ETF में कुल 42,300 करोड़ रुपये आए, जो पूरे 2024 के 18,600 करोड़ से दोगुने से भी ज्यादा है। इसी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो केवल 38,900 करोड़ रहा।

निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF सबसे बड़ा फंड बना हुआ है (AUM 18,500 करोड़), उसके बाद SBI गोल्ड ETF (15,200 करोड़) और HDFC गोल्ड ETF (12,800 करोड़) हैं। एक औसत गोल्ड ETF ने पिछले एक साल में 48% और 2025 में अब तक 38% रिटर्न दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भू-राजनीतिक जोखिम और मुद्रास्फीति की आशंका के बीच गोल्ड ETF पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन का सबसे आसान और पारदर्शी तरीका बन गया है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि दिसंबर में भी 8,000-10,000 करोड़ का इनफ्लो आ सकता है, जिससे साल के अंत तक AUM 1.15 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यह ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय निवेशक अब सोने को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो का स्थायी हिस्सा मान रहे हैं।

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in